GEO IAS
It's about quality

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Friday, 16th August , 2024

Edition: International Table of Contents

Page 01 **Syllabus : GS 2 : भारतीय राजनीति**	प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में 'धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता' का आह्वान किया
Page 01 **Syllabus : GS 2 : शासन**	सौर ऊर्जा योजना को पुनर्जीवित करने के लिए ड्रोन मैपिंग द्वारा संचालित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म
Page 03 **Syllabus : GS 1 : भूगोल**	भारतीय खगोलविदों ने अगले सौर चक्र के आयाम की भविष्यवाणी करने के लिए नई विधि खोजी
Page 06 **Syllabus : GS 2 : भारतीय राजनीति और संविधान**	केंद्र ने कीटों के प्रबंधन के लिए नई AI-आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की
समाचार में शब्द	टैंटलम
Page 08 : संपादकीय विश्लेषण: **Syllabus : GS 2 and 3 : शासन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी**	कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने से इनकार करने का हठ
अंतर्राष्ट्रीय संगठन	विषय: सात का समूह (G7)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'समान नागरिक संहिता' (यूसीसी) शब्द के विपरीत 'धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता' की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

- शब्दावली में यह बदलाव एक धर्मनिरपेक्ष ढांचे के भीतर विविध व्यक्तिगत कानूनों को एकीकृत करने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण को रेखांकित करता है, जिसका उद्देश्य धार्मिक विविधता का सम्मान करते हुए कानूनी मानकों को एकीकृत करना है।

PM calls for 'secular civil code' in Independence Day speech

In his 11th successive address to the nation from the Red Fort, Modi seeks to do away with a 'communal civil code' and end discrimination on the basis of religion; he flags issue of women's safety, says forces of anarchy want to destabilise country

Nistula Hebbar
NEW DELHI

In his 11th successive Independence Day address from the ramparts of the Red Fort, Prime Minister Narendra Modi on Thursday gave a renewed push to the BJP's ideological aim of a Uniform Civil Code (UCC), reframing the idea as a "secular civil code" enshrined in the Constitution and a way of ensuring equality before the law for all.

"The Supreme Court has repeatedly discussed a Uniform Civil Code in India. A large section of the country believes, and it is true that in the civil code, what we have is a communal civil code. The need of the hour is a secular civil code. Only then will we be free of discrimination on the basis of religion. It is our duty to fulfil the vision of our Constitution makers," the Prime Minister said.

National narrative: Prime Minister Narendra Modi addressing the nation at the Red Fort on 78th Independence Day. R.V. MOORTHY

Besides the UCC, a large part of the PM's customary address touched on several contemporary issues that packed a strong criticism of the Opposition. Without naming the West Bengal government and the rape and murder of a doctor in Kolkata, Mr. Modi flagged the issue of women's safety.

"Our mothers, sisters and daughters are being tortured. There is anger among the people and I can feel it. The country, society and State governments need to take this seriously. There must be quick investigation and conviction of the perpetrators of such crimes," he said.

Mr. Modi also referred to forces of anarchy that wanted to destabilise the country, especially economically, again an unnamed reference to the report by Hindenburg Research on the Adani Group, which BJP spokespersons have termed an attempt to destabilise Indian markets.

He reiterated his commitment to fighting corruption and deplored what he termed the tendency in some quarters to celebrate corruption. He added that he was prepared to pay the price for going after corruption and the corrupt.

Call for peace

On Bangladesh, the PM struck a pragmatic note. "As a neighbouring country, I understand the worry regarding what happened in Bangladesh. I hope that the situation becomes normal there very soon. We are committed towards peace and have the best wishes for Bangladesh's development journey," he said.

The PM also touched on the controversy surrounding the National Eligibility-cum-Entrance Test (NEET) for medical education, promising that his government would be increasing the seats available for medical education across the country by 75,000.

While delivering his longest Independence Day speech in 11 years (at 98 minutes), Mr. Modi also presented a report card of his government of the past 10 years, lauding the pace and intent of reforms undertaken by it.

MORE REPORTS
» PAGE 2,3, 4 & 5
FREEDOM NOTES
» PAGE 8

NDA allies strike a cautious note

NEW DELHI
The Janata Dal (U) and Telugu Desam Party, key allies of the ruling NDA, struck a cautious note on Prime Minister Narendra Modi's proposal for a "secular civil code". Both parties have not supported the idea in the past. » PAGE 5

धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता

- धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता से तात्पर्य ऐसे कानूनों के समूह से है जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और भरण-पोषण जैसे व्यक्तिगत मामलों को सभी नागरिकों के लिए समान रूप से नियंत्रित करता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, लेकिन इसे धर्मनिरपेक्ष, गैर-धार्मिक संदर्भ में तैयार किया जाता है।
- इसका उद्देश्य विविध धार्मिक प्रथाओं और विश्वासों के प्रति सम्मान बनाए रखते हुए एक समान कानूनी मानक बनाना है।

समान नागरिक संहिता

- यूसीसी सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को कवर करने वाले कानूनों का एक समान समूह प्रस्तावित करता है।
- समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के भाग IV में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार "नागरिकों के लिए पूरे भारत क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी।"
- समान नागरिक संहिता राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है, जो कानून द्वारा लागू नहीं होते हैं, लेकिन देश के शासन के लिए मौलिक हैं।
- सुप्रीम कोर्ट के विचार: सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन का आह्वान किया है।
  o 1985 के अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम मामले में, जहाँ एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला ने अपने पूर्व पति से भरण-पोषण की माँग की थी, न्यायालय ने यह तय करते हुए कि सीआरपीसी या मुस्लिम पर्सनल लॉ को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
  o न्यायालय ने सरकार से 1995 के सरला मुद्गल मामले और 2019 के पाउलो कॉउटिन्हो बनाम मारिया लुइज़ा वैलेंटिना परेरा मामले में समान नागरिक संहिता को लागू करने का भी आग्रह किया।
- वर्तमान में, समान नागरिक संहिता केवल गोवा में लागू है, जबकि उत्तराखंड में एक विधेयक पर विचार किया जा रहा है।

धर्मनिरपेक्ष और समान नागरिक कानूनों की तुलना

- **धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता**
- समावेशीपन: इसे एक समान कानूनी ढाँचा स्थापित करते हुए धार्मिक विविधता का सम्मान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- लचीलापन: यह कुछ संदर्भों में धार्मिक-विशिष्ट प्रथाओं की अनुमति दे सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत कानून के मुख्य पहलू सभी धर्मों में सुसंगत हों।
- उद्देश्य: यह व्यक्तिगत मामलों में प्रथाओं में सामंजस्य स्थापित करते हुए कानून में धर्मनिरपेक्षता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करता है।

समान नागरिक संहिता (यूसीसी)

- मानकीकरण: यह कानूनों का एक ऐसा सामान्य समूह प्रस्तावित करता है जो धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों को पूरी तरह से बदलकर सभी नागरिकों पर लागू होने वाले एकल कानूनी कोड से बदल देता है।
- एकरूपता: यह कानूनी मामलों में धार्मिक भेदभाव को खत्म करने का प्रयास करता है, तथा एकल कानूनी मानक को बढ़ावा देता है।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण कानूनी एकरूपता लाना है।

UPSC Prelims PYQ : 2012

प्रश्न: भारत के संविधान में निहित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें:

1. भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना
2. ग्राम पंचायतों का आयोजन करना
3. ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना
4. सभी श्रमिकों के लिए उचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना

उपर्युक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में परिलक्षित होते हैं?

(a) केवल 1, 2 और 4
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

GEO IAS
It's about quality

Page 01 : GS 2 : Governance : e-Governance

पीएम-कुसुम योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा संयंत्र और पंप स्थापित करके कृषि में सौर ऊर्जा को बढ़ाना है।

- हालांकि, देरी और भूमि उपलब्धता जैसी चुनौतियों ने प्रगति को बाधित किया है।
- इन मुद्दों को हल करने और योजना को आगे बढ़ाने के लिए ड्रोन तकनीक और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जैसे अभिनव समाधानों का उपयोग किया जा रहा है।

Digital platform driven by drone mapping to revive solar power scheme

Jacob Koshy
NEW DELHI

With delays plaguing the ₹34,000-crore PM-KUSUM programme launched to boost solar energy infrastructure in agriculture, States have begun experimenting with alternative approaches to improve adoption. The Pradhan Mantri-Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (PM-KUSUM) envisages setting up 100 GW of solar power plants in farmer-owned land, installing 14 lakh solar pumps, and solarising 35 lakh grid-connected agricultural pumps.

As of June, only 256 MW of power plants, 3.97 lakh solar pumps and 13,500 solarised pumps have been installed. The low uptake has forced the government to push the scheme's deadline to 2026.

A lot of challenges

A key hurdle is the unavailability of suitable land. Solar power in India has grown on the back of utility-scale power projects in Gujarat and Rajasthan where vast tracts of deserts and uncultivable land are suitable for setting up power plants.

With agricultural land, it is often a challenge to find enough parcels of land that can be pooled together and made available to a power project developer, said Saurabh Kumar, Vice President-India, Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP). The latter is a collaboration of the IKEA Foundation, the Rockefeller Foundation and the Bezos Earth Fund, and works on clean energy adoption and financing the transition away from fossil fuel in developing countries.

A key hurdle hindering the programme is the lack of suitable land. GETTY IMAGES

Drone technology

"We have been working with the Rajasthan government by developing a digital platform that uses drone technology to map land parcels. While this is information that is available to the government, often there is little institutional capacity to actually execute projects," said Mr. Kumar. "We connect with farmers and power developers."

"As of date, 12.3 MW has already been installed in Rajasthan. The plan is to touch 100 MW in 2024," said Mr. Kumar. Plans are afoot to apply this approach in Maharashtra and Madhya Pradesh as well, he added.

The digital platform allows tracking the scheme's progress in real-time allowing for "prompt corrective actions and provides a level of oversight crucial for the successful deployment of large-scale solar projects, where delays and mismanagement can have significant repercussions," a GEAPP document noted.

Farmers willing to set up solar modules on their lands are paid rent by the power project developer. "GEAPP looks to ensure that landowners receive fair compensation, with lease rates linked to prevailing market rates and adjusted for inflation. GEAPP's digital solutions and on-ground support have helped mitigate these issues, enabling Rajasthan to lead in achieving its renewable energy targets," according to the document. According to the Ministry for New and Renewable Energy (MNRE), of the 256 MW installed nationally, nearly 200 MW of solar capacity is situated in Rajasthan alone.

पीएम-कुसुम

- योजना का शुभारंभ: कृषि क्षेत्र में डी-डीज़लीकरण और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 2019 में शुरू किया गया।
- नोडल मंत्रालय: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)।
- उद्देश्य: ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना और भारत के 2030 के लक्ष्य को पूरा करना, जिसमें गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली क्षमता का 40% शामिल है।
- क्षमता वृद्धि: मार्च 2026 तक 34,800 मेगावाट सौर क्षमता जोड़ने का लक्ष्य।
- वित्तीय सहायता: कुल 34,422 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता।
- सब्सिडी: स्टैंडअलोन सोलर पंप और ग्रिड से जुड़े पंपों के सोलराइजेशन के लिए 30% या 50% तक की सब्सिडी।
- ग्रिड से जुड़े प्लांट: बंजर/परती भूमि पर 2 मेगावाट तक के सोलर प्लांट लगाने की अनुमति देता है।

घटक:

- घटक ए: 2 मेगावाट तक के छोटे सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से 10,000 मेगावाट। घटक बी: ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों के लिए 20 लाख स्टैंडअलोन सौर पंप।
- घटक सी: 15 लाख ग्रिड से जुड़े पंपों का सौरीकरण।
- पात्र संस्थाएँ: व्यक्तिगत किसान, समूह, एफपीओ, पंचायतें, सहकारी समितियाँ और जल उपयोगकर्ता संघ।

पीएम-कुसुम का परिचय और इसके उद्देश्य

- प्रधानमंत्री-किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना कृषि में सौर ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य किसान-स्वामित्व वाली भूमि पर 100 गीगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना, 14 लाख सौर पंप स्थापित करना और 35 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सौरकृत करना है।
- जून 2024 तक, प्रगति धीमी रही है, केवल 256 मेगावाट बिजली संयंत्र, 3.97 लाख सौर पंप और 13,500 सौर पंप स्थापित किए गए हैं, जिसके कारण समय सीमा 2026 तक बढ़ा दी गई है।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- एक बड़ी चुनौती सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उपयुक्त भूमि की अनुपलब्धता है, विशेष रूप से कृषि क्षेत्रों में जहाँ भूमि के समीपवर्ती टुकड़े मिलना मुश्किल है।
- गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों के विपरीत, जिनके पास बंजर भूमि का विशाल क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र बड़े पैमाने पर सौर परियोजनाओं के लिए भूमि जुटाने के लिए संघर्ष करते हैं।

नवीन दृष्टिकोण: ड्रोन प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म

- ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट (GEAPP) राजस्थान सरकार के साथ मिलकर एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म विकसित कर रहा है जो भूमि के टुकड़ों को मैप करने के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग करता है, जिससे सौर परियोजनाओं के लिए भूमि की पहचान की दक्षता बढ़ जाती है।
- यह डिजिटल दृष्टिकोण योजना की प्रगति की वास्तविक समय पर नज़र रखने की अनुमति देता है, जिससे त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई संभव होती है और बड़े पैमाने पर सौर परिनियोजन के लिए महत्वपूर्ण निगरानी प्रदान होती है।

राजस्थान में सफलता और भविष्य की योजनाएँ

- राजस्थान पीएम-कुसुम योजना में अग्रणी बनकर उभरा है, जहाँ पहले से ही 12.3 मेगावाट सौर क्षमता स्थापित है और 2024 तक 100 मेगावाट तक पहुँचने की योजना है।
- जो किसान सौर मॉड्यूल के लिए अपनी ज़मीन पट्टे पर देते हैं, उन्हें बाज़ार दरों से जुड़ा किराया भुगतान मिलता है, जिससे उचित मुआवज़ा सुनिश्चित होता है।

निष्कर्ष

- राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित 256 मेगावाट में से लगभग 200 मेगावाट स्थापित किया है, जो अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण है।
- जीईएपीपी द्वारा डिजिटल समाधानों और ऑन-ग्राउंड समर्थन का उपयोग चुनौतियों पर काबू पाने और पीएम-कुसुम योजना के तहत नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है।

UPSC Prelims PYQ : 2015

प्रश्न: भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है/हैं?

1. यह एक सार्वजनिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है।
2. यह एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

GEO IAS
It's about quality

Page 03 : GS 1 : Geography

भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के खगोलविदों ने एक नई विधि का उपयोग करके सौर चक्र पूर्वानुमान में एक बड़ी सफलता हासिल की है।

- 100 वर्षों के डेटा का विश्लेषण करके, उन्होंने पाया कि सौर न्यूनतम के दौरान सुपरग्रेनुलर कोशिकाओं की चौड़ाई बाद के सौर अधिकतम में सनस्पॉट संख्याओं से जुड़ी हुई है, जिससे अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणियों में सुधार हुआ है।

Indian astronomers find new method to predict amplitude of next solar cycle

The Hindu Bureau
BENGALURU

Astronomers from the Indian Institute of Astrophysics (IIA) have found a new method to predict the amplitude of the upcoming solar cycle. Besides, their research can also help in space weather forecasting.

The astronomers have discovered a new correlation using 100 years of solar data from the IIA's Kodaikanal Solar Observatory.

The intricacies of the solar cycle and forecasting space weather are important fields of current research, including in India.

The astronomers have discovered a new correlation using 100 years of solar data. TAMILNADUTOURISM.TN.GOV.IN

What is space weather?

"The main components of space weather are the solar wind, coronal mass ejections, and solar flares. They can compress the magnetosphere of the Earth and trigger geomagnetic storms, which can affect communication and power transmission, damage spacecraft electronics, and threaten the lives of astronauts. Thus, space weather has a profound influence on modern civilization," said the Department of Science and Technology.

Astronomers use many different ways to forecast the strength of the next solar cycle. This includes theoretical calculations based on dynamo models, extrapolations, precursor methods, etc.

The precursor method uses the value of some measure of solar activity at a specified time to predict the strength of the following solar maximum.

Number of sun spots

In a recently-published work, IIA researchers discovered that the width of the supergranular cells on the solar surface during the minimum year of the solar cycle is related to the number of sunspots seen during the subsequent solar cycle maximum. This simple method can be used in space weather forecasting.

समाचार के बारे में:

- भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA) के खगोलविदों ने सौर चक्र के आयाम की भविष्यवाणी करने और अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान में सुधार करने के लिए एक नई विधि विकसित की है।
- कोडाईकनाल सौर वेधशाला से 100 वर्षों के सौर डेटा पर आधारित उनके शोध से एक नया सहसंबंध सामने आया है।
- सौर हवा, कोरोनल मास इजेक्शन और सौर फ्लेयर्स से प्रभावित अंतरिक्ष मौसम, पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर को प्रभावित कर सकता है, जिससे संचार, बिजली प्रणाली, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
- पूर्वानुमान विधियों में सैद्धांतिक गणना, डायनेमो मॉडल और पूर्ववर्ती विधियाँ शामिल हैं।

- पूर्वानुमान विधि भविष्य के सौर मैक्सिमा की ताकत का अनुमान लगाने के लिए सौर गतिविधि उपायों का उपयोग करती है।
- IIA शोधकर्ताओं ने पाया कि सौर न्यूनतम के दौरान सौर सतह पर सुपरग्रेनुलर कोशिकाओं की चौड़ाई अगले सौर अधिकतम में सनस्पॉट की संख्या से संबंधित है, जो एक नया पूर्वानुमान उपकरण प्रदान करता है।

सौर चक्र

- सौर चक्र लगभग 11 वर्ष की अवधि है, जिसके दौरान सूर्य की चुंबकीय गतिविधि में उतार-चढ़ाव होता है, जिसमें सनस्पॉट, सौर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन में बदलाव शामिल हैं।
- चक्र सौर न्यूनतम से शुरू होता है, जो कम सौर गतिविधि और कुछ सनस्पॉट का चरण होता है, और सौर अधिकतम तक बढ़ता है, जिसमें सनस्पॉट की संख्या में वृद्धि और सौर गतिविधि में वृद्धि होती है।
- यह चक्र अंतरिक्ष मौसम को प्रभावित करता है, जो पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर और आयनमंडल को प्रभावित करता है।
- सौर चक्र अंतरिक्ष मौसम की घटनाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो उपग्रह संचालन, संचार प्रणालियों और यहां तक कि पृथ्वी पर बिजली ग्रिड को भी प्रभावित कर सकते हैं।

UPSC Prelims PYQ : 2022

प्रश्न: यदि कोई बड़ा सौर तूफान (सौर ज्वाला) पृथ्वी पर पहुँचता है, तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से संभावित प्रभाव हो सकते हैं?

1. GPS और नेविगेशन सिस्टम विफल हो सकते हैं।
2. भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में सुनामी आ सकती है।
3. पावर ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं।
4. पृथ्वी के अधिकांश भाग पर तीव्र ऑरोरा हो सकता है।
5. ग्रह के अधिकांश भाग पर जंगल में आग लग सकती है।
6. उपग्रहों की कक्षाएँ बाधित हो सकती हैं।
7. ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर उड़ने वाले विमानों का शॉर्टवेव रेडियो संचार बाधित हो सकता है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(a) केवल 1, 2, 4 और 5
(b) केवल 2, 3, 5, 6 और 7
(c) केवल 1, 3, 4, 6 और 7
(d) 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7

उत्तर: c)

Page 06 : Prelims Fact

केंद्र सरकार ने किसानों को मोबाइल फोन के माध्यम से कृषि वैज्ञानिकों से जोड़कर कीटों का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए एआई द्वारा संचालित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली (NPSS) शुरू की।

- इस प्रणाली का उद्देश्य कीटनाशकों के दुरुपयोग को कम करना, कीट नियंत्रण में सुधार करना और फसल की पैदावार को बढ़ाना है, जिससे पूरे भारत में लगभग 14 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे।

Centre launches new AI-based surveillance system to manage pests

NPSS will connect agriculture scientists with farmers; agriculturists can take a photo of infested crops or the insect using the system on their phones and this will reach scientists and experts

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Union government on Thursday launched the National Pest Surveillance System (NPSS) powered by artificial intelligence (AI) to help farmers to connect with agriculture scientists and experts by mobile phones for controlling pests.

Launching the programme, Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan said the aim was to reduce the dependence of farmers on pesticide retailers and to inculcate a scientific approach among them towards pest management. The NPSS will analyse latest data using AI tools to help farmers and experts in pest control and management.

Releasing the system at an event at the Indian Council of Agricultural Research, Mr. Chouhan said, "All new developments in the field of agriculture should be beneficial for the farmers." He added that increasing yield was a priority for the Modi government. "Farmers need better seeds for increasing productivity. Our scientific community is working along with the farmers towards this," he said.

Tech solution: The AI-based system will help in identifying pests and controlling them. A.M. FARUQUI

'For fast solution'

He said technology should reach the fields, and the NPSS was such an effort. "If we get to know about the pest attack at the beginning of the attack, it will help in finding a fast cure. This system will help in identifying pests and controlling them. The benefit of this technology must go to farmers," the Minister said.

The Ministry said the NPSS would help about 14 crore farmers in the country. The Centre envisages connecting scientists with farmers using it. Farmers can take photos of the infested crops or the insect using the system on their phones and this will reach scientists and experts.

"Using the correct quantity of correct pesticide at the correct time is the challenge and this system will help farmers to address this challenge," Union Agriculture Secretary Devesh Chaturvedi told *The Hindu*.

He said it would also help in addressing the problem of using excessive pesticides. "This system can help cure diseases at the proper time using technology. It will help in accurate diagnosis and accurate treatment. This will build confidence among farmers and production will also increase. This can save the soil too. It is a technological platform and needs no additional funding," he said.

He added that the technology would be sent to the States and they can propagate this using their outreach programmes.

"We have succesfully done pilot schemes on this system and it was released based on proper trials," Mr. Chaturvedi said.

राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली (NPSS)

- एनपीएसएस एक एआई-आधारित प्लेटफॉर्म है जिसे सरकार ने 15 अगस्त, 2024 को लॉन्च किया है।
- यह किसानों को अपने फोन का उपयोग करके प्रभावी कीट नियंत्रण के लिए कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से जुड़ने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इसका उद्देश्य कीटनाशक खुदरा विक्रेताओं पर किसानों की निर्भरता को कम करना है।
- यह चयनित फसलों यानी चावल, कपास, मक्का, आम और मिर्च के लिए डेटा प्रदान करता है।

किसान इसका उपयोग कैसे करेंगे

- किसान एनपीएसएस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके संक्रमित फसलों या कीटों की तस्वीरें ले सकते हैं, जिनका विश्लेषण वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है।
- फिर वे सही समय पर कीटनाशक की सही मात्रा का सुझाव देंगे, जिससे अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग कम होगा।
- लक्ष्य समूह: पूरे भारत में लगभग 14 करोड़ किसान।

महत्व

- यह फसल क्षति को कम करेगा, कीट प्रबंधन प्रथाओं में सुधार करेगा और अत्यधिक कीटनाशक के उपयोग को कम करके मिट्टी के नुकसान के जोखिम को कम करेगा।

GEO IAS
It's about quality

Term In News : Tantalum

केंद्र सरकार ने हाल ही में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची के भाग डी में टैंटालम सहित 24 खनिजों की सूची को महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के रूप में अधिसूचित किया है।

टैंटलम के बारे में:

- यह एक दुर्लभ धातु है जिसका प्रतीक Ta और परमाणु संख्या 73 है।
- घटना: कच्चा टैंटलम प्रकृति में शायद ही कभी पाया जाता है। इसके बजाय, यह आम तौर पर अयस्क कोलम्बाइट-टैंटलाइट (आमतौर पर कोल्टन के रूप में संदर्भित) में पाया जाता है।
- प्रमुख उत्पादक: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, रवांडा, ब्राजील और नाइजीरिया।

गुण:

- संक्रमण धातु के रूप में वर्गीकृत, टैंटलम कमरे के तापमान पर एक ठोस है।
- यह एक चमकदार, चांदी जैसी धातु है जो शुद्ध होने पर नरम होती है।
- यह 150 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर रासायनिक हमलों के लिए लगभग प्रतिरक्षित है।

- टैंटलम अपनी सतह पर एक ऑक्साइड फिल्म के कारण जंग के लिए लगभग प्रतिरोधी है।
- शुद्ध होने पर, टैंटलम नमनीय होता है, जिसका अर्थ है कि इसे बिना टूटे पतले तार या धागे में खींचा, खींचा या खींचा जा सकता है।
- यह धातुओं के एक वर्ग से संबंधित है जिसे दुर्दम्य धातु के रूप में जाना जाता है, जिसे गर्मी और पहनने के लिए उनके मजबूत प्रतिरोध द्वारा परिभाषित किया जाता है।
- इसका गलनांक बहुत अधिक है, जो केवल टंगस्टन और रेनियम से अधिक है।

अनुप्रयोग:

- इसका सबसे प्रमुख उपयोग इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में किया जाता है।
- टैंटलम से बने कैपेसिटर किसी भी अन्य प्रकार के कैपेसिटर की तुलना में बिना किसी रिसाव के छोटे आकार में अधिक बिजली संग्रहीत करने में सक्षम हैं।
- यह उन्हें स्मार्टफोन, लैपटॉप और डिजिटल कैमरों जैसे पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग के लिए आदर्श बनाता है।
- चूंकि टैंटलम का गलनांक अधिक होता है, इसलिए इसे अक्सर प्लैटिनम के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है, जो अधिक महंगा होता है।
- इसका उपयोग रासायनिक संयंत्रों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, हवाई जहाजों और मिसाइलों के लिए घटक बनाने के लिए भी किया जाता है।
- यह शारीरिक तरल पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है और इसका उपयोग कृत्रिम जोड़ों जैसे सर्जिकल उपकरण और प्रत्यारोपण बनाने के लिए किया जाता है।
- टैंटलम कार्बाइड (TaC) और ग्रेफाइट से बना एक मिश्रण सबसे कठोर सामग्रियों में से एक है और इसका उपयोग उच्च गति वाले मशीन टूल्स के कटिंग एज पर किया जाता है।.

UPSC Prelims PYQ : 2012

प्रश्न: हाल ही में, 'दुर्लभ पृथ्वी धातु' नामक तत्वों के समूह की कम आपूर्ति पर चिंता व्यक्त की गई है। क्यों?

1. चीन, जो इन तत्वों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ने इनके निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं।
2. चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चिली के अलावा, ये तत्व किसी अन्य देश में नहीं पाए जाते हैं।
3. दुर्लभ पृथ्वी धातुएँ विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक हैं और इन तत्वों की माँग बढ़ रही है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

उत्तर: c)

Page: 08 Editorial Analysis

An obstinate refusal to focus on welfare

Mohit Verma

Senior Research Associate at Good Business Lab, Bengaluru, specialising in labour and development economics

Shravan M.K.

Research Associate at the Centre for Sustainable Employment, Azim Premji University, Bengaluru

The National Democratic Alliance, in its third term, appears to be continuing the trend it set earlier — reducing budgetary allocations for welfare

The Union Budget has drawn stern criticism from several quarters of the populace for a variety of reasons. On the welfare front, the government has, yet again, failed to increase expenditure on critical welfare schemes that support the marginalised in the country. The government's obstinate refusal to focus on welfare is perplexing to say the least, in a country where, according to the government's own data, about 34% of the population survives on less than ₹100 a day and over 81 crore people require free foodgrains to get by. The National Democratic Alliance (NDA) now, or NDA 3.0, appears to continue the trend the alliance set in its two previous terms by reducing welfare allocations – as shown in the analysis below based on Budget papers.

Key welfare schemes, an underfunding

Two of the government's biggest welfare schemes, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) and the National Food Security Act (NFSA) (Food Subsidy) have seen their Budget allocations continuously fall as a share of GDP since 2014-15, except for the COVID-19 pandemic years when the government had to rely on these two schemes to avert a major disaster. MGNREGA guarantees every rural household 100 days of employment whereas the Food Subsidy is responsible for providing free foodgrains to about two-thirds of the population.

The NFSA had an expenditure of 0.72% of GDP last year, whereas this year, it has fallen to 0.63% of GDP. A truly bizarre decision in a country where over 100 crore people cannot afford a healthy diet and where just about 50% have three meals a day.

Similarly, the allocated budget for MGNREGA this year is 0.26% of GDP as compared to the 0.29% allocated last year. As a share of GDP, these two schemes today have a 25% lesser combined Budget allocation than they did in 2014-15 when the NDA first assumed power. With stagnating rural real wages and systematic underfunding of MGNREGA, it is no wonder that rural distress is spiking across the country.

Vulnerable groups such as widows, the elderly, and disabled individuals below the poverty line too were ignored in the Budget. The National Social Assistance Programme, which provides monetary support to the groups mentioned as well as families who have lost their breadwinner, saw no increase in its allocation in the Budget. Its Budget allocation this year is exactly the same as last year in nominal terms. Its expenditure as a share of GDP has halved since 2014-15, from 0.06% to 0.03%.

The scheme provides paltry pensions of ₹200 a month to the elderly and ₹300 a month to widows – an amount that has not increased since 2006 despite repeated requests from dozens of economists. Even at a poverty line of ₹30 a day, these vulnerable groups would be living at least 66% below the poverty line if left solely to the devices of the state.

Welfare and nutrition schemes

Recently, the Women and Child Development Minister admitted in Parliament that more than 50% of children under the age of five in India suffer from chronic malnutrition. Moreover, anaemia rates in Indian women and children are 20% and 15% higher, respectively, than the global average. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 is a welfare scheme which aims to tackle child malnutrition and hunger. The Anganwadi programme was merged with the Prime Minister's Overarching Scheme for Holistic Nourishment (POSHAN) Abhiyaan and a nutrition scheme for adolescent girls in 2021-22. However, even with additions, the Budget allocated for the same has declined by more than half since 2014-15 – from 0.13% of GDP then to 0.06% of GDP in the recent Budget.

To address malnutrition and hunger among school-going children, the government runs the mid-day meal (MDM) programme. The MDM programme covers about 12 crore children in the country. Despite the programme's many successes in increasing class attendance, and educational as well as nutritional outcomes, the funds meant for it have halved since 2014-15 as a share of GDP. Further, the Ministry of Finance rejected a plan for breakfast at school in 2021 citing a lack of funds despite the promise it has shown in Tamil Nadu.

In the face of an acute malnutrition crisis facing our children, it is imperative that we increase the coverage of these programmes and provide more nutritious food to our children.

The share in GDP of central expenditure on education (primary and secondary) has also declined this year to 0.22% from 0.25% last year. Although primary education enrolment rates are high, we still have a long way to go when it comes to education quality and basic infrastructure among other things. Thus, it is concerning when education's share in GDP falls from 0.37% in 2014-15 to 0.22% today.

The only saving grace here seems to be the Budget allocation for health, which saw a slight increase. Since 2014-15, the share of the Budget allocated to the Health Ministry in terms of GDP has increased from 0.25% then to 0.28% this year. The increase, however, is far from enough in a country where out-of-pocket expenditure on health remains very high and pushes millions into poverty every year.

The Budget allocation for all the mentioned schemes/departments has gone down from 2.1% as a share of GDP in 2014-15 to just 1.53% this year. The fact that the same was nearly thrice of what it is today – 4.31% of GDP – in the COVID-19 pandemic year of 2020-21, underlines the vitality of these schemes.

According to one estimate, the government has foregone tax revenue of over ₹8 lakh crore since it slashed corporate tax rates in 2019. It appears that it is the poor and the vulnerable who have been sacrificed to accommodate the resulting reduction in fiscal space due to tax cuts.

It is no wonder then that India has a poor Human Development Index rank of 132, and that today it is more unequal than it was during British rule, according to a new report by the World Inequality Lab.

In contrast, the UPA era

If the NDA government is serious about its Viksit Bharat dreams then it must realise that the way to a developed society is through the stomachs and pens of its poorest citizens. No civilised society could be considered developed if a large portion of its population is unable to afford a life of dignity. Perhaps, the NDA government would do well to follow the example of the United Progressive Alliance governments which not only saw the introduction of new welfare schemes but also a steady increase in their Budget allocations over time.

GS Paper 02 : शासन

GS Paper 03 : विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी : विभिन्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में जागरूकता

(UPSC CSE (M) GS-3 : 2023) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की अवधारणा का परिचय दें। AI नैदानिक निदान में कैसे मदद करता है? क्या आपको स्वास्थ्य सेवा में AI के उपयोग से व्यक्ति की गोपनीयता को कोई खतरा महसूस होता है? (150 words/10m)

Practice Question : हाल के कॉर्पोरेट प्रशासन रुझानों के संदर्भ में, एआई प्रौद्योगिकियों के विकास में लाभ कमाने और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने की चुनौतियों और निहितार्थों पर चर्चा करें। (150 w/10m)

संदर्भ :

- लेख कॉर्पोरेट प्रशासन में, विशेष रूप से AI विकास में, लाभ कमाने और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच तनाव पर चर्चा करता है।
- यह गोपनीयता संबंधी चिंताओं और एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रहों जैसी चुनौतियों का पता लगाता है, यह जांचता है कि OpenAI और Anthropic जैसी कंपनियां लाभ-संचालित बाजार में इन मॉडलों की स्थिरता पर सवाल उठाते हुए वैकल्पिक शासन संरचनाओं को कैसे अपना रही हैं।

शेयरधारक प्रधानता बनाम हितधारक दृष्टिकोण

- पारंपरिक कॉर्पोरेट प्रशासन में शेयरधारक प्रधानता के सिद्धांत का बोलबाला रहा है, जहां व्यवसायों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना और शेयरधारकों के लिए धन बनाना है।
- इसके विपरीत हितधारक लाभ दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य सभी हितधारकों के लिए लाभ को अधिकतम करना है, न कि केवल शेयरधारकों के लिए।
- हाल ही में, हितधारक पूंजीवाद ने जोर पकड़ा है, जिसमें निगम लाभ कमाने के साथ-साथ सामाजिक उद्देश्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, विशेष रूप से जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे क्षेत्रों में।

डेटा गोपनीयता और पूर्वाग्रह के मुद्दे

- AI प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा तक पहुंच की आवश्यकता होती है, जो गोपनीयता संबंधी चिंताओं को जन्म देती है।
- उदाहरण: Facebook और Instagram से सार्वजनिक सामग्री का उपयोग करने के बारे में आयरिश गोपनीयता नियामक द्वारा उठाई गई चिंताओं के कारण मेटा को यूरोप में अपने AI मॉडल प्रशिक्षण को रोकने के लिए कहा गया था।
- एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह एक और महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, जहाँ मानवीय पूर्वाग्रहों को AI सिस्टम में शामिल किया जा सकता है।
- उदाहरण: Amazon ने लैंगिक पूर्वाग्रह की खोज के बाद एक भर्ती एल्गोरिदम को बंद कर दिया, और प्रिंसटन विश्वविद्यालय के एक प्रयोग ने AI के शब्द संघों में नस्लीय पूर्वाग्रहों को उजागर किया।

शासन संरचनाएँ और संघर्ष

- AI से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए, कुछ कंपनियों ने जिम्मेदार AI विकास को प्राथमिकता देने के लिए अपने कॉर्पोरेट प्रशासन संरचनाओं को बदल दिया है।
- उदाहरण: एंथ्रोपिक के पास लॉन्ग-टर्म बेनिफिट ट्रस्ट नामक एक शासन संरचना है, जो वित्तीय रूप से उदासीन सदस्यों से बनी है जो बोर्ड के निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।
- ओपनएआई ने शुरू में एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में शुरुआत की, लेकिन बाद में अपने पूंजी-गहन नवाचार का समर्थन करने के लिए एक सीमित लाभ-सहायक कंपनी के साथ एक हाइब्रिड मॉडल में परिवर्तित हो गई।

उद्देश्य और लाभ के बीच टकराव: ओपनएआई की पराजय

- यहां तक कि वैकल्पिक शासन मॉडल वाली कंपनियों को भी सामाजिक उद्देश्य और लाभ कमाने के बीच संतुलन बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- उदाहरण: ओपनएआई ने एक शासन संकट का अनुभव किया जब इसके गैर-लाभकारी बोर्ड ने उपयोगकर्ता सुरक्षा से समझौता करने वाले तेजी से AI व्यावसायीकरण की चिंताओं के कारण सीईओ सैम ऑल्टमैन को निकाल दिया। इस कदम का माइक्रोसॉफ्ट और अधिकांश कर्मचारियों ने विरोध किया, जिसके कारण ऑल्टमैन को बहाल किया गया और बोर्ड को बदल दिया गया।
- इस घटना ने टेक उद्योग में सार्वजनिक लाभ निगमों की व्यवहार्यता के बारे में सवाल खड़े कर दिए हैं, जहाँ शेयरधारकों से वित्तीय सहायता महत्वपूर्ण है।

फ्राइडमैन का दृष्टिकोण: सामाजिक जिम्मेदारी से ज़्यादा लाभ

- 1970 में, मिल्टन फ्रीडमैन ने तर्क दिया कि किसी व्यवसाय की प्राथमिक सामाजिक जिम्मेदारी अपने शेयरधारकों के लिए लाभ उत्पन्न करना है।
- ओपनएआई जैसी कंपनियों में हाल की घटनाओं से पता चलता है कि सार्वजनिक लाभ संरचनाएँ सामाजिक हित को वास्तव में प्राथमिकता देने के बजाय केवल लाभ-प्राप्ति के उद्देश्यों को छिपा सकती हैं।

रणनीतिक समाधान: लाभ और सामाजिक उद्देश्य को संतुलित करना

- वर्तमान जवाबदेही संरचनाएँ, जिनमें स्वतंत्र बोर्ड नियुक्त करना और सामाजिक लाभ उद्देश्यों को अपनाना शामिल है, लाभ-संचालित लक्ष्यों की ओर अनैतिक बहाव से बचाने के लिए अपर्याप्त हैं।
- नीति निर्माताओं को ऐसे अभिनव विनियामक तरीके खोजने चाहिए जो एआई विकास में परस्पर विरोधी हितों को संतुलित करें।

लक्ष्यित करने के लिए तीन प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं:

- सामाजिक उद्देश्य को प्रोत्साहित करना: यह सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियाँ विकसित करने की आवश्यकता है कि सामाजिक लाभों का पीछा करना कंपनियों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय लाभ में भी योगदान देता है।
- प्रबंधकीय अनुपालन: प्रबंधकों को लाभ उद्देश्यों के साथ-साथ सार्वजनिक लाभ लक्ष्यों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहनों को संरेखित किया जाना चाहिए।

- अनुपालन लागतों को कम करना: विनियमनों और अनुपालन लागतों को सुव्यवस्थित करने से वित्तीय व्यवहार्यता से समझौता किए बिना सामाजिक लाभ उद्देश्यों को अपनाने में सुविधा हो सकती है।
- इस दृष्टिकोण में AI शासन के लिए नैतिक मानकों को तैयार करना और कॉर्पोरेट प्रशासन सुधारों के माध्यम से नियामक समर्थन प्रदान करना शामिल होगा।

निष्कर्ष:

- जीवन के विभिन्न पहलुओं में AI की बढ़ती भागीदारी के साथ, ऐसे शासन मॉडल को अपनाना महत्वपूर्ण है जो AI के नैतिक विकास को बढ़ावा देते हुए लाभ भी कमाते हैं।
- AI में प्रभावी शासन के लिए सामाजिक जिम्मेदारी और लाभ कमाने के बीच एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता होती है, जिसे नवीन और नियामक ढांचे द्वारा समर्थित किया जाता है।

शासन क्या है?

- 1993 में, विश्व बैंक ने शासन को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जिसके माध्यम से किसी देश के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संसाधनों को उसके विकास के लिए प्रशासित किया जाता है।
- शासन वह पद्धति और संस्थाएँ हैं जिनके माध्यम से किसी देश के भीतर निर्णय लिए जाते हैं और सत्ता का प्रयोग किया जाता है।
- शासन को विभिन्न परिस्थितियों में नियोजित किया जा सकता है, जिसमें कॉर्पोरेट प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रीय सरकार और स्थानीय शासन शामिल हैं।
- परिणामस्वरूप, शासन निर्णय लेने और निर्णय-कार्यान्वयन में शामिल औपचारिक और अनौपचारिक खिलाड़ियों और संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करता है।

शासन में भागीदार

- शासन में सरकार एक महत्वपूर्ण अभिनेता है। अन्य संभावित प्रतिभागियों में राजनीतिक अभिनेता और संस्थान, हित समूह, नागरिक समाज, मीडिया, गैर-सरकारी संगठन और अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल हैं।
- शासन में अन्य प्रतिभागी सरकार के स्तर के अनुसार भिन्न होते हैं। सामान्य तौर पर, राष्ट्रीय स्तर पर शासन के हितधारकों को तीन बुनियादी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:
  1. राज्य
  2. बाजार
  3. नागरिक समाज
- राज्य में कई सरकारी संस्थाएँ (विधानमंडल, न्यायपालिका और कार्यपालिका) और उनके संबंधित साधन, स्वतंत्र जवाबदेही प्रणाली आदि शामिल हैं। इसमें कई खिलाड़ी (निर्वाचित अधिकारी, राजनीतिक अधिकारी, नौकरशाही/विभिन्न स्तरों पर नागरिक कर्मचारी आदि) भी शामिल हैं।
- बाजार में संगठित और असंगठित दोनों तरह के निजी क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें विशाल कॉर्पोरेट घराने और छोटे आकार के उद्योग/प्रतिष्ठान शामिल हैं।
- नागरिक समाज सबसे अधिक विविधतापूर्ण है और इसमें अक्सर वे सभी संगठन शामिल होते हैं जो (ए) या (बी) में शामिल नहीं होते हैं। गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), स्वैच्छिक संगठन (वीओ), मीडिया संगठन/संघ, ट्रेड यूनियन, धार्मिक समूह, दबाव समूह आदि शामिल हैं।

शासन के कई महत्वपूर्ण पहलू हैं जो भारत में यूपीएससी सीएसई (सिविल सेवा परीक्षा) के लिए प्रासंगिक हैं। इनमें शामिल हैं:

- कानून का शासन: कानून का शासन शासन का एक सिद्धांत है जो सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्ति और संस्थाएँ कानून के अधीन हों और उससे बंधे हों। यह सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देता है, नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है, और सरकार में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।
- शक्तियों का पृथक्करण: शक्तियों का पृथक्करण एक सिद्धांत है जो सरकार की शक्तियों को विभिन्न शाखाओं (जैसे विधायी, कार्यकारी और न्यायिक) के बीच विभाजित करता है ताकि किसी एक शाखा में बहुत अधिक शक्ति के संकेंद्रण को रोका जा सके। यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि कोई भी शाखा बहुत शक्तिशाली न हो और अन्य शाखाओं की शक्ति पर जाँच के रूप में कार्य न कर सके।
- पारदर्शिता: सरकार में पारदर्शिता इस विचार को संदर्भित करती है कि सरकारी प्रक्रियाएँ और निर्णय लेना जनता के लिए खुला और सुलभ होना चाहिए। यह सरकार में जवाबदेही और विश्वास को बढ़ावा देने के साथ-साथ भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग को रोकने में मदद करता है।
- जवाबदेही: जवाबदेही के लिए सरकारी अधिकारियों और संस्थानों को अपने कार्यों और निर्णयों के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सरकारी कार्य लोगों की ज़रूरतों और चिंताओं के प्रति उत्तरदायी हों और सरकार में विश्वास को बढ़ावा दें।
- जवाबदेही: जवाबदेही सरकार की नागरिकों की जरूरतों और चिंताओं का जवाब देने की क्षमता है। यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सरकार की कार्रवाइयाँ बदलती परिस्थितियों के प्रति उत्तरदायी हों और अपने नागरिकों की उभरती जरूरतों को पूरा करें।
- भागीदारी: भागीदारी नागरिकों के लिए उन निर्णयों में अपनी बात रखने और राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होने का अवसर है जो उन्हें प्रभावित करते हैं। यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में समाज के सभी सदस्यों के विचारों और जरूरतों को ध्यान में रखा जाए और नागरिकों के बीच स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया जाए।
- समावेशीपन: समावेशिता यह विचार है कि समाज के सभी सदस्यों को उनकी पृष्ठभूमि या पहचान की परवाह किए बिना राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने और लाभ उठाने का समान अवसर मिलना चाहिए। यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि समाज के सभी सदस्यों की आवाज़ और दृष्टिकोण सुने जाएँ और नीतियाँ और निर्णय पूरे समुदाय की ज़रूरतों और चिंताओं को प्रतिबिंबित करें।
- कुशल और प्रभावी सेवा वितरण: सेवा वितरण से तात्पर्य सरकार द्वारा नागरिकों को आवश्यक सेवाओं (जैसे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बुनियादी ढाँचा) के प्रावधान से है। कुशल और प्रभावी सेवा वितरण यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि नागरिकों को समय पर और प्रभावी तरीके से उनकी ज़रूरत की सेवाएँ मिल सकें।
- सामाजिक न्याय: सामाजिक न्याय समाज में निष्पक्षता और समानता की खोज है, जिसमें संसाधनों और अवसरों का उचित वितरण शामिल है। यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि समाज के सभी सदस्यों को सफल होने और फलने-फूलने का समान अवसर मिले।
- पर्यावरणीय स्थिरता: पर्यावरणीय स्थिरता यह विचार है कि विकास को इस तरह से किया जाना चाहिए जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण करे। यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि निर्णय लेते समय वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाए।

कॉर्पोरेट प्रशासन क्या है?

- **इसके बारे में:**
  - o कॉर्पोरेट प्रशासन नियमों और प्रक्रियाओं का समूह है जो यह बताता है कि किसी कंपनी का प्रबंधन और देखरेख कैसे की जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि व्यवसाय नैतिक रूप से और इसमें शामिल लोगों के सर्वोत्तम हितों में संचालित हों। कॉर्पोरेट प्रशासन का एक प्राथमिक लक्ष्य कॉर्पोरेट लालच को रोकना और जिम्मेदार और पारदर्शी व्यावसायिक प्रथाओं को बढ़ावा देना है।

o उच्च नैतिक मानकों को स्थापित करने और लागू करने और व्यक्तियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने के द्वारा, कॉर्पोरेट प्रशासन कदाचार के खिलाफ सुरक्षा के रूप में कार्य करता है, शेयरधारकों, ग्राहकों और व्यापक समुदाय के हितों की रक्षा करता है।

- **कॉर्पोरेट प्रशासन के सिद्धांत:**

o निष्पक्षता: निदेशक मंडल को शेयरधारकों, कर्मचारियों, विक्रेताओं और समुदायों के साथ निष्पक्ष और समान विचार के साथ व्यवहार करना चाहिए।

o पारदर्शिता: बोर्ड को शेयरधारकों और अन्य हितधारकों को वित्तीय प्रदर्शन, हितों के टकराव और जोखिमों जैसी चीजों के बारे में समय पर, सटीक और स्पष्ट जानकारी प्रदान करनी चाहिए।

-

o जोखिम प्रबंधन: बोर्ड और प्रबंधन को सभी प्रकार के जोखिमों और उन्हें नियंत्रित करने के सर्वोत्तम तरीके का निर्धारण करना चाहिए। उन्हें उन्हें प्रबंधित करने के लिए उन सिफारिशों पर कार्य करना चाहिए। उन्हें जोखिमों के अस्तित्व और स्थिति के बारे में सभी संबंधित पक्षों को सूचित करना चाहिए।

o जिम्मेदारी: बोर्ड कॉर्पोरेट मामलों और प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।

· इसे कंपनी के सफल, चल रहे प्रदर्शन के बारे में पता होना चाहिए और उसका समर्थन करना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी का एक हिस्सा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की भर्ती करना और उसे नियुक्त करना है। इसे कंपनी और उसके निवेशकों के सर्वोत्तम हितों में कार्य करना चाहिए।

o जवाबदेही: बोर्ड को कंपनी की गतिविधियों के उद्देश्य और उसके आचरण के परिणामों की व्याख्या करनी चाहिए। यह और कंपनी का नेतृत्व कंपनी की क्षमता, संभावना और प्रदर्शन के आकलन के लिए जवाबदेह हैं। इसे शेयरधारकों को महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बताना चाहिए।

- **कॉर्पोरेट प्रशासन के चार P:**

o लोग: यह 'P' कॉर्पोरेट प्रशासन में शामिल व्यक्तियों के महत्व पर जोर देता है, जिसमें निदेशक मंडल, कार्यकारी और कर्मचारी शामिल हैं। बोर्ड की संरचना, उनके कौशल, स्वतंत्रता और विविधता महत्वपूर्ण कारक हैं।

o उद्देश्य: उद्देश्य कंपनी के व्यापक मिशन और लक्ष्यों को संदर्भित करता है। कॉर्पोरेट प्रशासन सुनिश्चित करता है कि कंपनी का उद्देश्य नैतिक मानकों के अनुरूप हो और शेयरधारकों और हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य बनाने पर केंद्रित हो।

o प्रक्रियाएँ: इस 'P' में कंपनी की देखरेख और प्रबंधन के लिए स्थापित प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं। शासन प्रक्रियाओं में शामिल हैं कि कैसे निर्णय लिए जाते हैं, जोखिम का आकलन और प्रबंधन कैसे किया जाता है, और जवाबदेही कैसे बनाए रखी जाती है।

o अभ्यास: कॉर्पोरेट प्रशासन में प्रदर्शन नैतिक मानकों का पालन करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कंपनी की समग्र सफलता से संबंधित है। शासन ढांचा स्थापित बेंचमार्क के विरुद्ध कंपनी के प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन करता है।

Group of Seven

ग्रुप ऑफ़ सेवन (G7)

- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसका गठन 1975 में हुआ था।
- वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे साझा हितों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए यह ब्लॉक सालाना बैठक करता है।
- सभी G7 देश और भारत G20 का हिस्सा हैं।
- G7 के पास कोई औपचारिक चार्टर या सचिवालय नहीं है। हर साल सदस्य देशों के बीच बारी-बारी से अध्यक्षता करने वाला यह संगठन एजेंडा तय करने का प्रभारी होता है। शिखर सम्मेलन से पहले शेरपा, मंत्री और दूत नीतिगत पहलों पर विचार करते हैं।
- 49वां G7 शिखर सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया था।

- यूरोपीय संघ (EU) एक संप्रभु सदस्य राज्य नहीं है। इसके बजाय, यह एक अद्वितीय सुपरनैशनल संगठन है। नतीजतन, EU को "गैर-गणना" सदस्य माना जाता है और यह G7 की अध्यक्षता नहीं करता है। G7 देशों के नाम नीचे सूचीबद्ध हैं:

G7 देशों की सूची

1. जर्मनी
2. कनाडा
3. फ्रांस
4. संयुक्त राज्य अमेरिका
5. यूनाइटेड किंगडम
6. इटली
7. जापान

- **सात के समूह का उद्देश्य**
- G7 देशों का लक्ष्य ऊर्जा नीति, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक आर्थिक नियंत्रण सहित विषयों पर चर्चा करना है। G7 वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करता है और उपरोक्त मुद्दों पर एक शक्तिशाली उत्प्रेरक है।

G7 डिजिटल व्यापार सिद्धांत

- 22 अक्टूबर, 2021 को G7 ट्रेड ट्रैक में, G7 देशों ने डिजिटल व्यापार सिद्धांतों को अपनाया। डिजिटल व्यापार सिद्धांतों में निष्पक्ष और समावेशी वैश्विक शासन, खुले डिजिटल बाजार, सीमा पार डेटा प्रवाह, उपभोक्ताओं, श्रमिकों और उद्यमों और उद्यमों के लिए सुरक्षा उपाय और डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म शामिल थे।

G7 का मुख्यालय

- G7 बिना किसी औपचारिक संधि के संचालित होता है और इसमें स्थायी सचिवालय या कार्यालय का अभाव होता है। इसके बजाय, यह एक घूर्णन प्रेसीडेंसी प्रणाली के तहत कार्य करता है, जिसमें सदस्य देश हर साल बारी-बारी से प्रेसीडेंसी संभालते हैं।

GEO IAS It's about quality

G7 का अवलोकन

- G7 देश नीति-निर्माताओं, नेताओं और मंत्रियों के बीच खुली चर्चा के लिए एक मंच हैं।
- G7 वैश्विक नेतृत्व प्रदान करता है और वैश्विक नेताओं और क्षेत्रीय सदस्यों द्वारा उठाए जाने वाले विषयों के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।
- G7 सदस्य देशों के रूप में दुनिया की औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएँ व्यापक चुनौतियों का समाधान करने और वैश्विक रुझानों को आकार देने के लिए एक साथ आती हैं।
- G7 ने लैंगिक समानता और जलवायु परिवर्तन सहित महत्वपूर्ण वैश्विक विषयों पर बहस को आगे बढ़ाया है, दाताओं को एक साथ लाया है और निरस्त्रीकरण परियोजनाओं का समर्थन किया है। इसने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सुरक्षा नीति को भी सुदृढ़ किया है।
- हर साल, सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित क्रम में G7 की अध्यक्षता करते हैं: फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा। रोटेशन में यूरोपीय संघ शामिल नहीं है।
- G7 देशों की जीडीपी रैंकिंग: शिखर सम्मेलन के आंकड़ों के अनुसार, G7 राष्ट्र 2022 में दुनिया भर की आबादी का 10%, वैश्विक जीडीपी का 31% और वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का 21% हिस्सा होंगे।

- चीन और भारत, दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं, जिनकी जीडीपी का अनुमान सबसे अधिक है, लेकिन उन्हें इस समूह से बाहर रखा गया है।
- 2021 में, सभी G7 देशों में वार्षिक सार्वजनिक क्षेत्र का खर्च राजस्व से अधिक होगा। अधिकांश G7 देशों में सकल ऋण का स्तर भी महत्वपूर्ण है, जिसमें अमेरिका (133%), जापान (GDP का 263%) और इटली (151%) शामिल हैं। G7 राष्ट्र विश्व व्यापार में महत्वपूर्ण भागीदार हैं।
- महत्वपूर्ण निर्यातक देश जर्मनी और अमेरिका हैं। 2021 में, दोनों कंपनियों ने एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निर्यात किया।

GEO IAS
It's about quality